शुक्रवार , 13 नवंबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

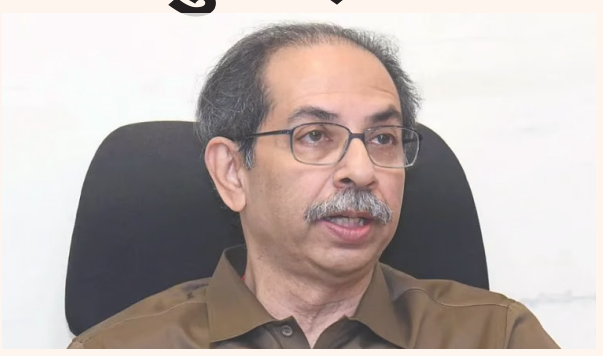
सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 77 CITY NEWS MUMBAI

विलय की अटकलों के बीच उद्धव का बड़ा कदम!

मातोश्री पर अचानक बुलाई विभाग प्रमुखों की बैठक

महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के विलय की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर मुंबई के सभी विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाई। जानिए क्या है बैठक का एजेंडा। विभाग प्रमुख स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच समन्वय बनाते हैं। स्मृति दिवस की तैयारियों के बहाने उद्धव ठाकरे का सीधा संवाद होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन और विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुंबई के सभी विभाग प्रमुखों की अचानक बैठक मातोश्री पर बुलाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के संभावित विलय और दोनों शिवसेनाओं के एक होने की अटकलों के बीच उद्धव की इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, बैठक का घोषित उद्देश्य आगामी 17 नवंबर को होने वाले शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के स्मृति दिवस की तैयारियों की समीक्षा करना है। स्मृति दिवस की तैयारियों पर होगी चर्चा हर साल 17 नवंबर को बालासाहेब ठाकरे के स्मृति दिवस पर मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित उनके स्मृति स्थल पर बड़ी संख्या में शिवसैनिक और अनुयायी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते हैं। इस बार भी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर



पार्टी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उद्धव ठाकरे ने इसी सिलसिले में मुंबई के सभी विभाग प्रमुखों को मातोश्री पर बुलाया है। बैठक में कार्यक्रम के सुचारू आयोजन, श्रद्धांजलि सभा की व्यवस्थाओं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और भीड़ प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जानी है। रा अटकलों के बीच संगठन की मजबूती पर जोर इन घटनाक्रमों के बीच उद्धव ठाकरे की विभाग प्रमुखों के साथ बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग प्रमुख पार्टी संगठन की अहम कड़ी होते हैं और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के बीच समन्वय बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैठक में स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की सक्रियता और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। स्मृति दिवस की तैयारियों के बहाने उद्धव ठाकरे का अपने संगठन के पदाधिकारियों से सीधा संवाद भी होगा। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन और विलय को लेकर अटकलें चल रही हैं, इस बैठक के बाद पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर भी नजरें रहेंगी। हालांकि, बैठक को किसी संभावित राजनीतिक विलय से जोड़ने का कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है। जनीतिक हलचल के बीच संगठन की समीक्षा महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से राकां के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच शिंदे गुट के कुछ नेताओं के बयानों से दोनों शिवसेनाओं के एक साथ आने की संभावना को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। सांसद ओमराजे निंबालकर ने कहा है कि यदि दोनों शिवसेनाएं एक साथ आती हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। वहीं, मंत्री भरत गोगावले ने फिलहाल ऐसी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।

महाराष्ट्र में NCP के विलय की चर्चा से महायुति में हलचल, CM देवेंद्र फडणवीस के बयान ने बढ़ाई सियासी उत्सुकता

NCP के दोनों गुटों के विलय की चर्चाएं तेज हैं। सुनेत्रा पवार के बयान के बाद CM देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि महायुति की सहमति के बिना कोई फैसला संभव नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार के NCP गुटों के संभावित विलय की चर्चा तेज। सुनेत्रा पवार ने 11 नवंबर को कहा कि उचित समय आने पर सब पता चल जाएगा। संभावित विलय से NCP के नेतृत्व और संगठनात्मक व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। फिलहाल दोनों गुटों की ओर से विलय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार



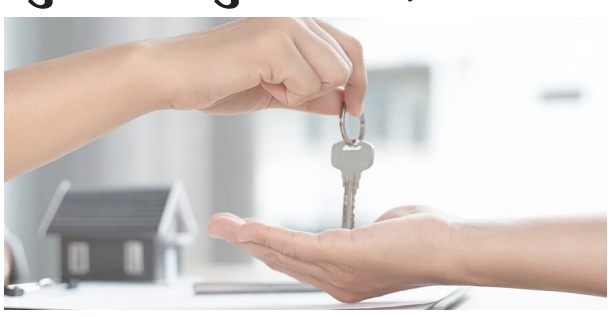
फिर नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चा ने राज्य की सत्तारूढ़ महायुति के भीतर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ शरद पवार और अजित पवार के गुटों के एक साथ आने की संभावनाओं पर नजरें टिकी हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रुख ने इस चर्चा को और महत्वपूर्ण बना दिया है। NCP के दोनों गुटों के बीच एकता की चर्चा नई नहीं है, लेकिन हाल के बयानों ने इसे फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। राजनीतिक बदलाव में महायुति के मौजूदा सत्ता समीकरण उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने 11 नवंबर को इस संबंध में कहा कि उचित समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। उनके इस बयान को दोनों गुटों के बीच संभावित बातचीत के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, अभी तक विलय को ...शेष 7 पर

धारावी में सभी को मिले 500 से 750 वर्गफुट के घर, पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ आजाद मैदान में प्रदर्शन



धारावी पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ 25 नवंबर को आजाद मैदान में महामोर्चा। बिना भेदभाव 500 और 750 वर्ग फुट के घर की मांग। धारावी पुनर्विकास के विरोध में 25 नवंबर को आजाद मैदान में महामोर्चा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना करेगी आंदोलन का नेतृत्व। झोपड़ीधारकों को 500 और चाल-स्लम निवासियों को 750 वर्गफुट घर देने की मांग। धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों का ...शेष 7 पर

किरायेदार मकान खाली नहीं कर रहा तो क्या करें? मुंबई पुलिस ने शुरू की नई व्यवस्थां



महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत मुंबई के सभी 15 जोन के डीसीपी सक्षम प्राधिकारी नियुक्त। अब मकान मालिक किरायेदार विवादों में उनके पास आवेदन कर सकेंगे। मुंबई पुलिस ने नए किराया नियंत्रण कानून के तहत पहली बार मामला दर्ज किया है। पश्चिम क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज शर्मा ने इस बड़ी कार्रवाई की पुष्टि की है। जोन-8 के पुलिस उपायुक्त निमित गोयल ने इस कानून के व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। मकान मालिकों को किरायेदारों से जुड़ी ...शेष 7 पर

सिंहगढ़ एजुकेशन सोसायटी पर हाईकोर्ट सख्त, 44 संस्थानों के फंड की CBI-ED जांच; खाते फ्रीज, 400 करोड़ की देनदारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी के खिलाफ CBI, ED और आयकर जांच के आदेश दिए। ट्रस्ट के खाते और संपत्तियां फ्रीज। सिंहगढ़ एजुकेशन सोसायटी के 44 संस्थानों की CBI, ED और आयकर विभाग से जांच के आदेश। 8 साल से वेतन बकाया, 12 से अधिक कर्मचारियों की आत्महत्या का हाईकोर्ट ने किया जिक्र। ट्रस्ट के बैंक खाते और निवेश फ्रीज, ट्रस्टियों की संपत्ति के लेन-देन पर रोक। महाराष्ट्र की सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (STES) के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों



को पिछले आठ वर्षों से वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने के मामले में अदालत ने संस्था के 44 शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय लेन-देन की जांच CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही संस्था और ट्रस्टियों के बैंक खाते तथा निवेश फ्रीज करने और संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने को कहा है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की विशेष पीठ ने करीब 220 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंधकीय ट्रस्टी मारुति नवले समेत आठ ट्रस्टियों को अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। 400 करोड़ रुपये से अधिक का वेतन बकाया अदालत के सामने कर्मचारियों की कुल बकाया राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई। पीठ ने कहा कि कई कर्मचारियों को आठ वर्षों से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक तंगी के कारण 12 से अधिक कर्मचारियों की आत्महत्या का भी आदेश में उल्लेख किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम भुगतान और पेंशन संबंधी लाभ भी नहीं ...शेष 7 पर

कश्मीर का 'लाल सोना' क्यों हो रहा है गायब? कौन है इसका पीछे का जिम्मेदार

कश्मीर का लाल सोना संकट में क्यों है? 10 साल में उत्पादन 8 टन से घटकर 2.6 टन कैसे हुआ और खेती पर कौन से खतरे मंडरा रहे हैं? कश्मीर में केसर का उत्पादन 8 टन से घटकर 2.6 टन कैसे पहुंचा? जलवायु परिवर्तन, साही-चूहों के हमलों से केसर की खेती को कितना नुकसान हो रहा है? ईरानी केसर के नाम पर मिलावट कैसे हो रही है? कश्मीर की पहचान सिर्फ खूबसूरत वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और झीलों तक सीमित नहीं है। यहां की एक और खास पहचान है, जिसे दुनिया 'लाल सोना' कहती है। हम बात कर रहे हैं कश्मीरी केसर की, जो अपनी खुशबू, गहरे लाल रंग और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन सदियों पुरानी यह खेती अब गंभीर संकट से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन, बारिश की कमी, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, जंगली जानवरों के हमले और नकली केसर की बिक्री ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में केसर का उत्पादन 2010-11 में 8 टन था, जो 2023-24 में घटकर महज 2.6 टन रह गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कश्मीर की यह अनमोल विरासत धीरे-धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रही है? आखिर क्यों खास है कश्मीर का केसर? कश्मीर के पंपोर को देश में केसर की खेती का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां की करेवा भूमि पर उगने वाला केसर अपनी गुणवत्ता और खुशबू के लिए जाना जाता है। इसे 'लाल सोना' भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमत दुनिया के सबसे महंगे मसालों में शामिल है। केसर क्रोकस सैटिवस नाम के बैंगनी फूल वाले पौधे से प्राप्त होता है। इसके प्रत्येक फूल में केवल तीन लाल रेशे होते हैं, जिन्हें हाथों से सावधानीपूर्वक निकालकर सुखाया जाता है। लगभग 28 ग्राम केसर तैयार करने के लिए करीब 4,000 फूलों की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इसकी खेती में काफी मेहनत और समय लगता है। कश्मीरी केसर में क्रोसिन की मात्रा अधिक होती है, जो इसे गहरा रंग प्रदान करती है। इसका इस्तेमाल मिठाइयों, पारंपरिक व्यंजनों, नून चाय, इत्र और पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। दस साल में 8 टन से घटकर 2.6 टन हुआ उत्पादन कश्मीर में केसर की खेती पर सबसे बड़ा संकट घटता उत्पादन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2010-11 में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में करीब 8 टन केसर का उत्पादन हुआ था। 2023-24 तक यह आंकड़ा गिरकर 2.6 टन रह गया। इस गिरावट के पीछे मौसम में बदलाव एक बड़ी वजह माना जा रहा है। केसर के पौधों को फूल आने से पहले अगस्त और सितंबर में पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है। इन महीनों में सूखा पड़ने से मिट्टी में नमी कम हो जाती है और फूलों की संख्या प्रभावित होती है। किसानों का कहना है कि पहले सर्दियां लंबी और ठंडी होती थीं, लेकिन अब बर्फबारी और बारिश का पैटर्न बदल रहा है।



ग्रैंड फिनाले से पहले बड़ा झटका, 15 देशों ने पीछे खींचे कदम; 6 एशियाई देशों पर लगा बैन

प्यूर्टो रिको में होने वाले 75वें मिस यूनिवर्स पेजेंट से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फ्रेंचाइजी विवाद और वीजा समस्याओं के चलते 15 देश इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। 75वां मिस यूनिवर्स पेजेंट प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में आयोजित हो रहा है । कॉरपोरेट विवादों के चलते थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और लाओस पर बैन। अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के कारण नेपाल समेत कई अफ्रीकी देशों की सुंदरियां भी हुईं बाहर। प्यूटो रिको के सैन जुआन में 75वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट की तैयारियां जोरों पर हैं। इंटरनेट पर हर तरफ जोस मिगुएल एग्रेलोट कोलिजियम की चकाचौंध और ब्यूटी पेजेंट्स की शानदार तस्वीरें छाई हुई हैं, लेकिन, चमक-दमक वाले इस ग्रैंड इवेंट में शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले 15 देशों ने इस ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट से अपना कदम पीछे खींच लिया है। 6 एशियाई देशों पर लगा बैन इस बार मिस यूनिवर्स के मंच पर थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और लाओस का जलवा देखने को नहीं मिलेगा। कॉरपोरेट और फ्रेंचाइजी से जुड़े आपसी विवादों के चलते इन 6 एशियाई देशों के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है। राहत की बात बस इतनी है कि इन देशों की ब्यूटी पेजेंट्स से उनका नेशनल टाइटल नहीं छीना जाएगा। एक दिलचस्प बात यह भी है कि वियतनाम भले ही इस साल बैन की वजह से हिस्सा नहीं ले पा रहा है, लेकिन अगले साल होने वाले 76 वें मिस यूनिवर्स की मेजबानी वियतनाम ही करने वाला है। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी काजिया मिस यूनिवर्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व काजिया लिज मेजो करेंगी, केरल के मावेलिक्कारा की रहने वाली 19 वर्षीय काजिया ने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने 52 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। काजिया लिज मेजो कौन है? काजिया सिर्फ मॉडल ही नहीं, बल्कि लॉ की पढ़ाई भी कर रही हैं। उनका बचपन अबू धाबी में बीता है। उन्हें क्लासिकल डांस का भी शौक है और वह करीब 12 साल तक इसकी ट्रेनिंग ले चुकी है। इसके अलावा उन्हें गाना गाने और ड्रम्स व वायलिन बजाने में भी दिलचस्पी है। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने से पहले काजिया मिस टीन दीवा 2024 का ताज भी जीत चुकी है। उन्होंने मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और फर्स्ट रनर-अप रही थीं। अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी नजर भारत के चौथे मिस यूनिवर्स खिताब पर होगी।



दिल्ली में AQI का मीटर 500 पर क्यों रुक जाता है? प्रदूषण तो 1000 के पार, 5 बड़े कारण जानें



दिल्ली में प्रदूषण 1,000 माइक्रोग्राम के पार पहुंचने पर भी AQI 500 पर क्यों रुक जाता है? CPCB ने सिस्टम की कौन सी तकनीकी खामी स्वीकार की है? CPCB ने माना कि 999 माइक्रोग्राम से अधिक PM प्रदूषण का डेटा मौजूदा सिस्टम में AQI की गणना में शामिल नहीं होता। दिल्ली के 59 में से 45 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर कम से कम एक प्रदूषक का घंटेवार डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। AQI की अधिकतम सीमा 500 क्यों है और 2015 में तैयार डेटा सत्यापन सिस्टम में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को लेकर एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है।

कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली में छाया कोहरा, अंडमान में भारी बारिश



पश्चिमी विक्षोभ के असर से 12 नवंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में भारी बर्फबारी, ओलावृष्टि और ऑरेंज अलर्ट जारी। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की चेतावनी। कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अनुमान है। पश्चिम और मध्य भारत में मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 12 नवंबर को पूरे भारत में वायुमंडलीय स्थितियां मुख्य रूप से एक सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' से प्रभावित रहेंगी। इस प्रणाली के तहत, निचले वायुमंडल में उत्तरी पाकिस्तान और उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' बना हुआ है। इसके साथ ही, ऊपरी वायुमंडल में एक 'ट्रफ' मौजूद है।

अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी: अमेरिका-दुबई से आएंगे बाराती, बिहटा में बहू के स्वागत के लिए बना नया आशियाना

बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिका और दुबई से भी बराती आएंगे, वहीं बिहटा स्थित नए घर में गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई। अनंत सिंह की बेटी की शादी में अमेरिका और दुबई से आएंगे बराती बिहटा के नए घर में गृहप्रवेश का कार्यक्रम सम्पन्न 20 नवंबर को दानापुर में तिलक और 25 नवंबर को नदवां में शादी सास आशा देवी का आया रिएक्शन-बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी बिहार के चर्चित नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों पूरे राज्य में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शाही शादी की तैयारियां न केवल बिहार बल्कि देश-विदेश तक में सुर्खियां बटोर रही हैं। शादी को यादगार और भव्य बनाने के लिए परिवार के लोग दिन-रात एक किए हुए हैं। वहीं होने वाले ससुराल पक्ष की तरफ से भी स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अमेरिका और दुबई से आ रहे कई विदेशी मेहमान शिवांगी सिंह की शादी में सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी खास मेहमान और बराती पहुंचने वाले हैं। शिवांगी के होने वाले ससुर रणविजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, सुकमा, मेरठ और दिल्ली के अलावा अमेरिका तथा दुबई में रहने वाले उनके दोस्त और परिचित भी इस शादी में शरीक होने आ रहे हैं। मीडिया में शादी की खबरें आने के बाद विदेशों से लगातार बधाई के फोन आ रहे हैं और लोग समारोह में शामिल होने के लिए बेहद उत्सुक हैं। बिहटा में बने नये आशियाने में गृह प्रवेश की पूजा संपन्न शादी के बाद बहू के पहले कदम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पटना के बिहटा में एक नया भव्य घर तैयार कराया गया है। बुधवार को इसी नए मकान में पूरे विधि-विधान और वैदिक रीति-रिवाजों के साथ गृह प्रवेश की पूजा आयोजित की गई। परिवार के सदस्य दिल्ली से बिहटा पहुंच चुके हैं और शादी से जुड़ी शुरुआती रस्मों की तैयारियों में जुट गए हैं। हल्दी समेत कई महत्वपूर्ण वैवाहिक रस्में इसी नए आशियाने में संपन्न की जाएंगी, जिसे लेकर परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। 20 नवंबर को तिलक और 25 नवंबर को आएगी बारात शादी के कार्यक्रमों की पूरी प्लान भी सामने आ चुका है। रस्मों की शुरुआत 20 नवंबर से होगी, जब पटना के दानापुर स्थित ऑर्गेनो बैंक्वेट हॉल में तिलक समारोह आयोजित किया जाएगा।



केजरीवाल को मिली धमकी निकली फर्जी, बिश्नोई गैंग के नाम से नहीं बल्कि रोहतक से किया गया था कॉल

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक बार फिर बड़ी धमकी सामने आई है। इस बार निशाने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता हैं। 6 नवंबर 2026 को व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल के जरिए दी गई धमकी। बिश्नोई गैंग का नाम लेकर मांगी गई 7 करोड़ रुपये की मोटी रकम। AAP विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस से की शिकायत, नंबर ट्रेस करने में जुटी पुलिस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले ने AAP विधायक जरनैल सिंह के जरिए 7 करोड़ रुपये की मांग की। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस को बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अरविंद केजरीवाल से 7 करोड़ रुपये की मांग की है। साथ ही, यह धमकी भी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वे केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मार देंगे। उनकी शिकायत के अनुसार, यह धमकी भरा कॉल और व्हाट्सएप मैसेज 6 नवंबर, 2026 को आया था। धमकी मामले में बड़ा



खुलासा अब अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मोहाली पुलिस के मुताबिक यह धमकी भरा कॉल फर्जी था। वहीं, पुलिस आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल, आईपी लॉग और लोकेशन की जांच कर रही थी। विधायक ने केजरीवाल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की थी। पुलिस जांच के दौरान धमकी वाला कॉल फर्जी पाया गया। कॉल करने वाला आदमी रोहतक का बताया जा रहा है। पार्टी को बदनाम करने की साजिश सूत्र के मुताबिक, कॉल करने वाला किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर फर्जी कॉल क्यों किया गया और इसके पीछे क्या मकसद था। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। पार्टी का आरोप है कि इस तरह के फर्जी कॉल के जरिए पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया मिली जानकारी के अनुसार, धमकी देने वाले आरोपी ने दिल्ली के तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह को फोन पर धमकी दी। आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया और व्हाट्सएप पर 7 करोड़ की फिरौती मांगी। आरोपी ने पैसे न देने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के खिलाफ विधायक जनरैल सिंह ने मोहाली के साइबर क्राइम थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

15 लाख का इनामी आतंकी लतीफ भट और 2 विदेशी दहशतगर्द! कुलगाम से किश्तवाड़ तक हाई अलर्ट, OGWs से पूछताछ जारी

कुलगाम में CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट का हाथ सामने आ रहा है। आतंकियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट भेदने वाली खास AP गोलियों का इस्तेमाल किया किश्तवाड़ में आतंकी हमले के दौरान लापता हुए दो एसपीओ के शव बरामद। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन। सीसीटीवी फुटेज और ओजीडब्ल्यू (OGW) के जरिए आतंकियों की तलाश तेज। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर आतंकी हमले के बाज इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दलदली इलाके से चलते हुए हमलावरों ने सीआरपीएफ के अखरान कैंप में नाका ड्यूटी पर तैनात जवानों पर एके47 राइफल से फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के बाद हमलावर झाड़ियों की आड़ में फरार हो गए। इस घटना में 3 जवान घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जवानों की



पहचान हेड कॉन्स्टेबल सोमवीर और कॉन्स्टेबल संतानो और राकेश दास के तौर पर हुई है। दो एसपीओ जवान शहीद आतंकियों की तार लश्कर के कमांडर लतीफ भट से जोड़े जा रहे है। साथ ही 2 विदेश आतंकी होने की संभावना जताई जा रही है। पूरे इलाके में तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना के दौरान लापता हुए दो एसपीओ जवान के शव गुरुवार सुबह बरामद किए गए। दोनों जवानों के शरीर में गोली के निशान पाए गए है। आतंकियों द्वारा दोनों एसपीओ को मारे जाने की संभावना बताई जा रही है। जवानों के पास मौजूद सरकारी हथियार भी गायब हो गए है। दक्षिण कश्मीर में चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे है। इसके जरिए हमलावरों की पहचान और उनके भागने का रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों ने किन खतरनाक गोलियों का इस्तेमाल किया? मिली जानकारी के अनुसार, कुलगाम में CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले में, आतंकवादियों ने खास तरह की मेटल-जैकेट वाली, आर्मर-पियर्सिंग (AP) गोलियों का इस्तेमाल किया। ये ऐसी गोलियां हैं जो बुलेटप्रूफ जैकेट को भी भेद सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, इनमें से कुछ गोलियां एक CRPF जवान की बुलेटप्रूफ जैकेट को भेद गईं थीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान का फिलहाल श्रीनगर में सेना के 92 बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। लतीफ भट पर लगे सनसनीखेज आरोप जांच एजेंसियों को इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ होने का संदेह है। पुलिस हमले के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। लतीफ भट पर 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या का आरोप है। इसके अलावा लतीफ पर 31 जुलाई को कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की हत्या में भी नाम शामिल है। पुलिस की माने तो वह एक घाटी में सक्रिय आतंकी है।

मनीला में मोदी और ट्रंप की जोड़ी चीन को दिखाएगी आईना, एक दौरे से सधेंगे दो बड़े निशाने



पीएम नरेंद्र मोदी की संभावित मनीला यात्रा से वैश्विक कूटनीति गरमा गई है। लगभग दो साल बाद QUAD नेताओं का महाजुटान होने जा रहा है, जिससे चीन की धड़कनें तेज होना तय माना जा रहा है। अबकी बार मनीला में होने जा रहा है QUAD नेताओं का महाजुटान। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की खास मुलाकात होने की चर्चा। जानिए कैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होगी समुद्री सुरक्षा। दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी पर रोक लगाने की योजना पर फोकस। भारत और फिलीपींस के रणनीतिक रिश्ते और भी मजबूत होने के बनेंगे आसार। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का एक बड़ा मंच पर जुटना हमेशा ही वैश्विक राजनीति की दिशा तय करता है। 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ASEAN शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ-साथ QUAD नेताओं की अहम बैठक में शामिल होने के लिए मनीला जा सकते हैं।

दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला; जानें क्या कहा?



क्या पोता जन्म से दादा की संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत क्या अहम फैसला सुनाया? दादा की संपत्ति में पोते के जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 और 1986 के पुराने फैसले का इस मामले में क्या महत्व है? चेन्नई की संपत्ति का विवाद कैसे शुरू हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार कितना होता है? क्या वह जन्म लेते ही दादा की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर दादा की संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत उनके कानूनी वारिसों के बीच हो चुका है, तो पोता केवल जन्म के आधार पर उसमें अपना स्वतंत्र हिस्सा नहीं मांग सकता।

रेलवे में 10वीं पास के लिए निकली बंपर भर्ती, न परीक्षा होगी न इंटरव्यू, जानें कैसे करें आवेदन

रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए 4651 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू, बिना परीक्षा कैसे होगा चयन? कौन आवेदन कर सकता है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है? नॉर्दर्न रेलवे में 4651 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 11 नवंबर से आवेदन शुरू। 10वीं में 50 प्रतिशत अंक जरूरी, 15 से 24 साल तक के युवा कर सकते हैं आवेदन। रेलवे भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, 10वीं के अंकों से बनेगी मेरिट लिस्ट। 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में ट्रेनिंग हासिल करने का अच्छा अवसर सामने आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), नॉर्दर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 4,651 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से शुरू हो गई



है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को किसी लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। उनका चयन 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। रेलवे किन जगहों पर होगी भर्ती? नॉर्दर्न रेलवे की यह अप्रेंटिस भर्ती कुल छह क्लस्टर के अंतर्गत निकाली गई है। इनमें दिल्ली, लखनऊ, अंबाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद और जम्मू शामिल हैं। कुल 4,651 पदों में सबसे ज्यादा 1,525 पद लखनऊ और 1,312 पद दिल्ली क्लस्टर में रखे गए हैं। इसके तहत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, स्टेनोग्राफर और डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत अलग-अलग ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। रेलवे अप्रेंटिस के लिए कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होंगी। 1. अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। 2. संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3. उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम उम्र 24 साल निर्धारित की गई है। 4. SC/ST वर्ग को अधिकतम उम्र में 5 साल और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। 5. दिव्यांग अभ्यर्थियों (PwBD) को अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी।

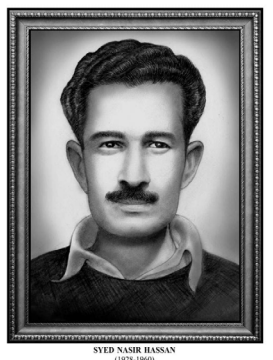
सम्पादकीय

अमेरिका की दुविधा या चीन का लाभ ?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और चिप्स के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। विश्व की शीर्ष अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के प्रमुख का चीनी जासूसी जाल में फंसना क्या मायने रखता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर और अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप्स अब वैश्विक शक्ति संतुलन में तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु हथियार और सैन्य शक्ति के समान ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। 21वीं सदी की विश्व महाशक्ति कौन होगी, इसका फैसला शायद युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि चिप निर्माण कारखानों, डेटा केंद्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशालाओं में होगा। अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष की बदलती प्रकृति इसका प्रमाण है। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, अग्रणी अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया और उसके प्रमुख जेन्सेन हुआंग के आसपास मंडरा रही जासूसी की आशंका वैश्विक प्रौद्योगिकी जगत को हिला रही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या चीन ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी साम्राज्य में घुसपैठ करके जीत हासिल कर ली है। सेमीकंडक्टर केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक घटक नहीं हैं। लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, उपग्रह, रडार, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारी, स्वचालित हथियार प्रणाली और आधुनिक युद्ध प्रणाली, ये सभी अत्याधुनिक चिप्स पर निर्भर करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से युद्धक्षेत्र की जानकारी का विश्लेषण, शत्रु की गतिविधियों का पूर्वानुमान, लक्ष्य की पहचान और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। इसलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में प्रभुत्व का अर्थ है भविष्य की सैन्य शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता। अमेरिका के पास चिप डिजाइन, अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, अनुसंधान और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों का एक विशाल नेटवर्क है। एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, क्वालकॉम जैसी कंपनियां इस प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। दूसरी ओर, चीन के पास विशाल विनिर्माण क्षमता, एक बड़ा घरेलू बाजार, सरकारी निवेश और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है। इसलिए यह प्रतिस्पर्धा अब किसी एक कंपनी या एक उत्पाद तक सीमित नहीं है। यह संपूर्ण प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र पर नियंत्रण की लड़ाई बन गई है। एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग और चीन से जुड़ी व्यवसायी अनलिस हुआंग उर्फ हुआंग ले के बीच कथित करीबी संबंधों ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है। सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी अनलिस हुआंग पर चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए जानकारी जुटाने का संदेह है। बताया जाता है कि मेगास्पीड ने दो वर्षों में लगभग 4.8 अरब डॉलर मूल्य के एनवीडिया चिप्स खरीदे हैं। इन लेन-देन के मद्देनजर, चीन को उन्नत चिप्स पहुंचाने के संभावित तरीकों की भी जांच शुरू कर दी गई है। जेन्सेन हुआंग ने विवाहेतर संबंध होने की बात स्वीकार की है और अपने परिवार और सहकर्मियों से माफी मांगी है। एनवीडिया के निदेशक मंडल ने एक स्वतंत्र जांच शुरू की है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यापारिक रहस्यों से संबंधित जानकारी लीक होने का कोई सबूत नहीं है। चीन ने भी जासूसी के आरोपों का खंडन किया है। इसलिए, एनलिस हुआंग के खिलाफ आरोपों या चीन की संलिप्तता के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। शेयरधारकों को गुमराह करने के आरोप में एनवीडिया और जेन्सेन हुआंग के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है। इस मामले में अब राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निवेशकों की विश्वसनीयता का आयाम भी जुड़ गया है। इस घटना का मुख्य बिंदु यह संभावना है कि चीन ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी नेतृत्व में संभावित कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की हो सकती है। हालांकि, यह चिंताजनक है कि चीन अमेरिकी प्रौद्योगिकी सुरक्षा प्रणाली के सामने गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका ने निर्यात प्रतिबंधों का इस्तेमाल करके चीन को उन्नत चिप्स और परिष्कृत चिप निर्माण उपकरणों तक पहुँचने से रोका है। नीदरलैंड्स में ASML की उन्नत लिथोग्राफी मशीनों, अमेरिकी चिप डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर और जापान के कुछ उपकरणों पर नियंत्रण चीन की प्रगति में प्रमुख बाधाएँ हैं। विशेष रूप से, चीन को EUV तकनीक तक आसानी से पहुँच नहीं है, जो उन्नत चिप निर्माण के लिए आवश्यक है। हालाँकि, इन प्रतिबंधों ने चीन की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त नहीं किया है। इसके विपरीत, हुआवेई, SMIC और अन्य घरेलू कंपनियों के माध्यम से घरेलू चिप निर्माण को गति देने के प्रयास जारी हैं। चीन पुरानी पीढ़ी की DUV मशीनों, चिप पैकेजिंग और घरेलू अनुसंधान के अधिक कुशल उपयोग के माध्यम से तकनीकी अंतर को कम करने का प्रयास कर रहा है। सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र द्वारा 2026 के एक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने चीन को अपने घरेलू प्रौद्योगिकी विकास में अधिक बढ़ावा दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चीन को अभी भी उन्नत चिप निर्माण, विनिर्माण परिशुद्धता, लिथोग्राफी, डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर और उच्च-प्रदर्शन GPU के क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, अमेरिका पर निर्भर हुए बिना एक वैकल्पिक प्रणाली बनाने की चीन की रणनीति दीर्घकालिक है। अमेरिका के लिए असली चिंता का विषय यही है। मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस में बहुमत हासिल कर लिया है। जनवरी 2027 से बदलते राजनीतिक समीकरण का असर एआई उद्योग की दिशा पर पड़ सकता है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने संकेत दिया है कि वे एआई कंपनियों के संचालन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, उन्नत एआई मॉडलों की स्वतंत्र सुरक्षा जांच करवाना चाहते हैं, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं और डेटा केंद्रों के कारण बढ़ती बिजली लागत के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। डेटा केंद्रों को भारी मात्रा में बिजली, पानी और जमीन की आवश्यकता होती है।

13 नवम्बर यौम-ए-वफात पर विशेष। स्वतंत्रता सेनानी सैय्यद नासिर हसन

देशद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सरकार द्वारा हिरासत में लिए गये आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिकों की रिहाई की मांग को लेकर छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सैय्यद नासिर हसन का जन्म 2 अगस्त, 1928 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था। उनके पिता सैय्यद आलम बरदार और माँ ज़ोहरा थीं। हसन की नानी फ़करुल हाजिया हसन एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनके मामा आबिद हसन सफ़रानी, बदरुल हसन, प्रो. जाफ़र हसन ने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हैदराबाद के सिटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नासिर ने 1946 में छात्र आंदोलन में प्रवेश किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा हिरासत में लिए


SYED NASIR HASSAN
(1928-1960)

गये आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिकों की रिहाई की मांग की गई थी। नासिर ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद निज़ाम राज्य के भारतीय संघ में विलय की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया, जिन्होंने हैदराबाद राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष के घर का घेराव किया और उनसे निज़ाम सरकार पर विलय के लिए दबाव बनाने की मांग की। जब निज़ाम पुलिस ने नलगोंडा जिले के सूर्यपेट में विलय समर्थक आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर दमनात्मक हमले किये, तो नासिर ने सितंबर 1946 में दमन के खिलाफ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद नासिर साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए। वे प्रगतिशील लेखक सज्जाद ज़हीर के निमंत्रण पर पाकिस्तान गये। उन्होंने किसानों और मज़दूरों की ओर से पाकिस्तान में जन आंदोलन का नेतृत्व किया। वे कम्युनिस्ट पार्टी, सिंध प्रांतीय शाखा के सचिव के पद तक पहुँचे। नासिर की जन-समर्थक गतिविधियों से नाराज़ पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने उन्हें दो साल के लिए निर्वासित कर दिया और उससे पहले उन्हें लगभग चार साल तक नज़रबंद रखा। निर्वासन की अवधि के दौरान, वे हैदराबाद पहुँचे और अपने माता-पिता के साथ समय बिताया। उस दौरान, वे परिवार को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए प्रचार से दूर रहे और निर्वासन की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान लौट आये। बाद में पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लाहौर किले की जेल में बंद कर दिया। और वहीं 13 नवंबर 1960 को सैय्यद नासिर हसन को जहर देकर मार दिया गय। संदर्भ- द इम्मोर्टल्स, सैय्यद नसीर अहमद द्वारा संकलन हसरत अली शेरपुर जिला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश

खोखला होता जा रहा है पाकिस्तान

तमाम चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों से गुलाम जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की गोलाबारी में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग विधानसभा में 'शरणार्थी सीटों' को खत्म करने की है। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान इन सीटों का इस्तेमाल मुजफ्फराबाद की स्थानीय सरकार में अपने पिट्ठुओं को बिठाने के लिए करता आया है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए जोइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी का गठन किया, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में जेएएसी ने 12वीं विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार किया। ऐसे माहौल में हुए चुनावों की कोई वैधता नहीं। जैसी उम्मीद थी, इन चुनावों में सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) की जीत हुई। गुलाम जम्मू-कश्मीर के साथ ही इमरान खान की लगातार हिरासत को लेकर खैबर-पख्तूनख्वा में भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इन विरोध-प्रदर्शनों का जवाब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहकर दिया कि मीरपुर और रावलकोट जैसे इलाकों के लोग कश्मीरी ही नहीं हैं। ध्यान रहे इसके पहले पाकिस्तान कश्मीर पर अपने दुष्प्रचार के लिए लंदन में बसे मीरपुरवासियों का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन जैसे ही इन इलाकों के स्थानीय लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग उठाई तो उनकी कश्मीरी पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। रक्षा मंत्री ने उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन तक बताकर उनकी तुलना भारत से की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की कुल 53 सीटें हैं। इनमें स्थानीय लोगों के लिए 33 सीटें, 12 शरणार्थी सीटें और महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स, मौलवियों तथा विदेश में रहने वाले यहां के लोगों के लिए आठ आरक्षित सीटें हैं। शरणार्थी सीटों से आशय उन सीटों से है, जो कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग से आए। अजीब बात यह है कि ये शरणार्थी यहां के निवासी न होकर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में इनकी सहभागिता से स्थानीय निवासियों और अन्य हिस्सों के लोगों के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। शरणार्थी सीटों में मतदाताओं की संख्या बहुत कम है और वे बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। इससे पाकिस्तानी सरकार के लिए चुनाव परिणामों में हेरफेर करना आसान हो जाता है और हर चुनाव में अधिकांश सीटों पर उसी दल की ही जीत होती है, जिसे पाकिस्तानी शासक जिताना चाहते हैं। ये चुनाव क्षेत्र कितने छोटे हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाल के चुनावों में एलए-43 निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,839 ही थी, जबकि अधिकतम मतदाताओं वाली एलए 45 सीट पर 4,271 ही मतदाता थे। इन सीटों की बदौलत पाकिस्तान सरकार को इस प्रांत की विधानसभा में 25 प्रतिशत की एकमुश्त वोटिंग मिल जाती है, जो सत्ता की चाबी अपने पास रखने में मददगार बनती है। प्रांतीय सरकार ने शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरणार्थी सीटें प्रांतीय संविधान द्वारा ही तय की गई हैं और उन्हें संविधान में परिवर्तन के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन में न पाकिस्तान को, न ही प्रांत की कठपुतली सरकार को कोई रुचि है। जो सरकार शरणार्थी सीटों के बल पर ही अस्तित्व में आई हो, वह भला इन सीटों को क्यों खत्म करेगी? इन चुनावों में पीएमएल-एन ने 31 सीटें जीतकर 53 सीटों के सदन में बहुमत हासिल किया। इनमें से 11 सीटें शरणार्थी सीटें हैं। उनके बिना उसका बहुमत ही खत्म हो जाएगा। अब गुलाम जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय दलों की कोई हैसियत नहीं बची, जबकि दशकों तक क्षेत्रीय दल ही यहां की सत्ता पर काबिज रहे।

पाकिस्तान के एक और अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर रूल घोषित कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि प्रांतीय सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ है और वहां बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों से न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे पाकिस्तान को खतरा है। इस प्रांत में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) सत्ता में है और वह उनकी रिहाई के लिए अभियान छेड़े हुए है। देखना यह है कि राष्ट्रपति के फैसले से वहां इमरान खान के पक्ष में मुहिम कमजोर पड़ती है या उनके प्रति समर्थन और बढ़ता है? इस प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच हाल में तनातनी बढ़ी है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की सरकार उसके यहां अशांति फैला रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को शह दे रही है। पाकिस्तानी सेना एक सीमा से अधिक यहां सख्ती भी नहीं कर सकती, क्योंकि फौज में पठानों की संख्या काफी अधिक है। पाकिस्तान के समक्ष मुश्किलें तब बढ़ रही हैं, जब वह कर्ज के बोझ से कराह रहा है। पाकिस्तानी रुपया डालर के सामने दम तोड़ता जा रहा है, जिससे उसकी आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिन हो रही है। केंद्र सरकार नए खर्चों के लिए पूरी तरह कर्जे पर निर्भर होती जा रही है, क्योंकि राजस्व के स्रोत सिकुड़ रहे हैं। इस सबके बाद भी वह अपनी भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।

पाकिस्तान के अघोषित शासक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर कितने ही प्रयास करें, लेकिन वे इस वास्तविकता को तो ओझल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की बुनियाद कमजोर हो रही है और वह खोखला होता जा रहा है। पिछले कुछ समय से ट्रंप की खुशामद कर रहे मुनीर के लिए शायद अब अमेरिकी राष्ट्रपति की चापलूसी भी काम न आए, क्योंकि मध्यावधि चुनाव के बाद खुद उनकी राह कठिन हो गई है।

प्यार करने वालो के लिए क्यो खास है 11:11 का दिन, जानें इस तारीख का महत्व



अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में शादी की। जानिए 11.11 तारीख का अंक ज्योतिष में महत्व, प्यार और नई शुरुआत से इसका खास कनेक्शन। म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर यानी 11.11 को शादी के लिए चुना। अंक ज्योतिष में 11 को मास्टर नंबर माना जाता है, जो अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। 11:11 को नई शुरुआत, प्यार और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना गया है। अनिरुद्ध ने शादी की तस्वीरों के साथ लिखा, 'My once in a lifetime, for a lifetime, 11.11'। आज म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। ग्रीस में समंदर किनारे हुई इस ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। शादी में अनिरुद्ध आइवरी कुर्ते और वेष्टि में नजर आए, जबकि काव्या मारन ब्लश पिंक लहंगे में बेहद खूबसूरत दिखाई दीं। दोनों के पारंपरिक और आकर्षक वेडिंग लुक की भी खूब चर्चा हो रही है। इस शादी में जहां एक तरफ कपल के रॉयल आउटफिट और रोमांटिक तस्वीरें सुर्खियों में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी की तारीख ने भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। बता दें कि दोनों ने 11 नवंबर यानी 11.11 को शादी की है। अंक ज्योतिष में इस तारीख को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर 11.11 को इतना खास क्यों माना जाता है और प्यार, शादी तथा लव-लाइफ की नई शुरुआत से इसका क्या संबंध है? 11.11 तारीख क्यों है खास? दरअसल 11 नवंबर की तारीख अपने खास अंकों की वजह से आकर्षक मानी जाती है। जब इसे 11.11 के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें 11 का अंक दो बार दिखाई देता है। अंक ज्योतिष में 11 को मास्टर नंबर कहा गया है। 11.11 को अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक समझ, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के लिए बेहद महत्वपुर्ण माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, यह अंक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने, खुद पर भरोसा रखने और जीवन में नए अवसरों को अपनाने की प्रेरणा देता है। यही वजह है कि कई लोग 11.11 की तारीख को किसी खास काम की शुरुआत के लिए शुभ मानते हैं। 11:11 का क्या अर्थ है? 11:11 को मुख्य रूप से एक 'एंजेल नंबर' और आध्यात्मिक संकेत के रूप में जाना जाता है, जिसे सकारात्मक बदलाव, नई शुरुआत और इच्छाओं के पूरा होने का प्रतीक माना जाता है। नंबर 1 को नई शुरुआत और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का संकेत माना जाता है। जब यह अंक चार बार (11.11) एक साथ आता है, तो इसे जीवन में नए और सकारात्मक अध्याय की मजबूत शुरुआत के रूप में देखा जाता है।

यंग डीएसए और स्काउट ओपी की दोस्ती में आयी दरार, इन कंटेस्टेंट्स पर लटकेगी नॉमिनेशन की तलवार



बिग बॉस 20 में टॉर्चर टास्क के दौरान स्काउट ओपी और यंग डीएसए के बीच जोरदार बहस देखने को मिलेगी। वहीं लव गिल पर कमेंट के बाद स्काउट को माफी मांगनी पड़ेगी। टॉर्चर टास्क में स्काउट ओपी और यंग डीएसए भिड़े लव गिल पर गलत कमेंट कर फंसे स्काउट, मांगी माफी बिग बॉस 20 में इस हफ्ते 10 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में आज का एपिसोड ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है। बिग बॉस में आज टॉर्चर टास्क देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बिग बॉस में इन कंटेस्टेंट्स के सिर पर नॉमिनेशन की तलवार लटकेगी। बिग बॉस 20 में आज दो जिगरी दोस्तों स्काउट ओपी और यंग डीएसए के बीच में जोरदार बहस होती हुई देखी जा सकती है। जियो हॉटस्टार के लेटेस्ट प्रोमो में इस जुबानी जंग की कुछ झलकियां भी देखने के लिए मिली है। हालांकि गूल्लू और घर के बाकी सदस्य आकर इस लड़ाई को रोकते हुए नजर आते है।

फिल्म कुर्बान के पोस्टर से लेकर कुरान आयात वाले पेडेंट तक, इन 6 विवादों से खराब हुआ करीना कपूर का नाम



करीना कपूर खान अपने अभिनय के साथ-साथ कई बार विवादों को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। जानें कुर्बान पोस्टर, ताज होटल, बिंदी और शाही पेंडेंट से जुड़े चर्चित मामले। करीना कपूर का 200 साल पुराने पेंडेंट पर विवाद कुर्बान पोस्टर से बिंदी विवाद तक, कई बार घिरीं सुर्खियों में ताज होटल झगड़े से ओरी संग तस्वीरों तक, जानें बड़े विवाद एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपने दिवाली लुक को सुर्खियों में है। अपने बोल्ड और ब्यूटीफुल लुक के लिए चर्चा में रहने वाली करीना कपूर इस समय एक नए विवाद में घिर गई है। दरअसल, करीना कपूर ने अपने दिवाली लुक के लिए 200 साल पुराना एक शाही पेंडेंट पहना था, जो भोपाल रियासत की बेगम और सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान की विरासत से जुड़ा था। हालांकि इस पेडेंट में कुरान की आयतें लिखी होने के कारण ये विवाद में बदल गई है। करीना कपूर से जुड़े विवाद फिल्म कुर्बान का पोस्टर (2009) साल 2009 में करीना कपूर की फिल्म कुर्बान के एक बोल्ड पोस्टर को लेकर शिवसेना और विभिन्न हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया था। उनका कहना था कि यह पोस्टर महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवसैनिक करीना कपूर के घर की ओर बढ़े ताकि उन्हें ओढ़ने के लिए साड़ी भेंट कर सकें लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हालांकि, इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद एक्ट्रेस का बयान भी सामने आया था। उनका कहना था कि यह फोटो फिल्म की थीम (जो आतंकवाद और गहरे जज्बात पर आधारित है) से जुड़ी हुई है और इसमें कुछ भी अश्लील या वल्गर नहीं है। ताज होटल विवाद (2012) 22 फरवरी 2012 को मुंबई के कोलाबा स्थित ताज होटल के वासाबी रेस्टोरेंट में सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और उनके कुछ दोस्त मौजूद थे। वहां पास की टेबल पर बैठे साउथ अफ्रीका के एनआरआई बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा ने ज्यादा शोर-शराबे को लेकर आपत्ति जताई थी। इस बात पर सैफ अली खान और इकबाल शर्मा के बीच जोरदार बहस हुई, जिसके बाद सैफ अली खान पर मारपीट का आरोप लगा। पुलिस ने सैफ और उनके दोस्तों को गिरफ्तार भी किया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई। लव जिहाद अभियान से जुड़ा मामला जनवरी 2015 में उत्तर भारत में दुर्गा वाहिनी द्वारा प्रकाशित पत्रिका हिमालय ध्वनि के कवर पर करीना कपूर की एक मॉर्फ्ड फोटो छपी थी। इस फोटो में उनका आधा चेहरा सामान्य और आधा चेहरा बुर्के से ढका हुआ दिखाया गया था। पत्रिका में इस तस्वीर के नीचे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की पंक्ति लिखी गई थी। दुर्गा वाहिनी की उत्तर भारत संयोजक और पत्रिका की संपादक रजनी ठुकराल के अनुसार, यह अभियान उन हिंदू लड़कियों की घर वापसी के लिए था जिन्होंने मुस्लिम युवकों से शादी की थी। मालाबार गोल्ड का विज्ञापन और बिंदी विवाद (अक्षय तृतीया) अप्रैल 2022 में अक्षय तृतीया के अवसर पर ज्वैलरी ब्रांड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा जारी किए गए एक विज्ञापन में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान के माथे पर बिंदी न होने के कारण सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

भारत और अफगानिस्तान के बीच खिताबी जंग की रेस, अफगानिस्तान ने जीता टॉस



मेन्स अंडर-19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। जानें दोनों टीमों की प्लेइंग-11 और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड। अंडर-19 एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज ओमान में भारत और अफगानिस्तान आमने-सामने हैं। अफगानिस्तान के कप्तान सोहेल खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। लक्ष्य राजेश रायचंदानी की कप्तानी में भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। एसीसी पुरुष अंडर-19 वनडे एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज यानी गुरुवार को भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। ओमान के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) में खेले जा रहे इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान सोहेल खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा यू-टर्न, मुस्तफिजुर रहमान समेत 7 खिलाड़ियों को मिला नीलामी का टिकट



IPL 2027 मिनी-ऑक्शन से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने यू-टर्न लिया है। पिछले विवादों को भुलाकर मुस्तफिजुर रहमान समेत 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे। बांग्लादेश बोर्ड ने बहिष्कार का पुराना फैसला बदल दिया है। पिछले साल के भारत-बांग्लादेश क्रिकेट तनाव को दरकिनार कर दिया गया है। मुस्तफिजुर रहमान समेत कुल 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी IPL 2027 मिनी-ऑक्शन में उतरेंगे। IPL 2027 की नीलामी से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपने पुराने रुख से पलटते हुए एक बड़ा 'यू-टर्न' लिया है। पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट को लेकर हुए तमाम विवादों और बहिष्कार की बातों को दरकिनार करते हुए अब मुस्तफिजुर रहमान समेत कुल 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी आगामी आईपीएल मिनी-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। इन 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान द्वारा नीलामी में भाग लेने की इच्छा जताए जाने के बाद बीसीबी ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीसीबी के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि मुस्तफिजुर के अलावा 6 अन्य प्रमुख क्रिकेटर भी नीलामी का हिस्सा बनेंगे। इस सूची में ये नाम शामिल हैं: मुस्तफिजुर रहमान तस्कीन अहमद तौहीद हृदॉय रिशाद हुसैन नाहिद राणा हसन महमूद शोरीफुल इस्लाम BCCI की पहल के बाद नरम पड़े बांग्लादेश के तेवर दरअसल, रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से संपर्क साधा था। इसके बाद ही बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों को एक बार फिर इस लीग में भेजने के लिए राजी हुआ है।

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग पर गाज गिरनी तय: WSJ की रिपोर्ट में क्या-क्या किया गया दावा

कंपनी के सह-संस्थापक और CEO जेनसन हुआंग विवाहेतर संबंधों व चीनी जासूसी विवाद के बाद बोर्ड उन्हें हटाने की तैयारी कर रहा है। Nvidia के CEO जेनसन हुआंग पर संकट के बादल बरकरार हैं। विवाहेतर संबंधों और जासूसी के गंभीर आरोप के बाद कुर्सी पर खतरा बना हुआ है। बोर्ड द्वारा पद से हटाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। शेयर बाजार में आई 8 प्रतिशत की गिरावट से कंपनी तमाम विकल्प खोज रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी Nvidia एक बहुत बड़े विवाद में फंस गई है। कंपनी के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसन हुआंग पर गाज गिरती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब जेनसन हुआंग को उनके पद से हटाने की गंभीर तैयारी कर रहा है। इस पूरी उथल-पुथल की मुख्य वजह उनके दो विवाहेतर संबंधों के खुलासे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक संदिग्ध चीनी जासूसी विवाद है, जिसने अमेरिकी कॉरपोरेट जगत में हड़कंप मचा दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक विशेष रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Nvidia का निदेशक मंडल कंपनी के सह-संस्थापक और CEO जेन्सन हुआंग को पद से हटाने की तैयारी कर रहा है। यह कदम हुआंग के



दो विवाहेतर संबंधों और संदिग्ध चीनी जासूसी कनेक्शन से जुड़े गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद कंपनी को होने वाले नुकसान के मद्देनजर उठाया जाने वाला है। चूंकि यह बड़ा फैसला है, इसलिए कंपनी का बोर्ड काफी सोच विचार कर यह फैसला ले रहा है और उनके विकल्प की भी तलाश की जा रही है। सिंगापुर की कार्यकारी के साथ संबंधों का खुलासा इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब सिंगापुर की एक डेटा कंपनी 'मेगास्पीड' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग के साथ जेनसन हुआंग के रिश्तों की बात सामने आई। मेगास्पीड कंपनी एनवीडिया की एक प्रमुख ग्राहक रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का गहरा संदेह है कि एलिस हुआंग चीन की खुफिया गतिविधियों से जुड़ी हुई थीं और वे एनवीडिया की बेहद उन्नत AI तकनीक से जुड़े राज चुराने की कोशिश कर रही थीं। जब यह बात बाहर आई, तो खुद जेनसन हुआंग ने कर्मचारियों को एक पत्र लिखकर अपनी गलती स्वीकार की और पत्नी के प्रति बेवफाई के लिए माफी मांगी। कंपनी की ही अधिकारी से दूसरे अफेयर का दावा मामला यहीं नहीं थमा, बल्कि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट ने इस आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेनसन हुआंग का केवल एक ही नहीं, बल्कि अपनी ही कंपनी की हेल्थकेयर विभाग की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी अफेयर रहा है, जो सीधे उनके अधीन काम करती थीं। कॉरपोरेट जगत के नियमों के मुताबिक, अपने ही अधीनस्थ कर्मचारी के साथ इस तरह के संबंध रखना कंपनी की आचार संहिता का एक बहुत बड़ा और गंभीर उल्लंघन माना जाता है, जिससे बोर्ड के सदस्यों में भारी नाराजगी है। स्वतंत्र जांच और अमेरिकी संसद का दबाव जैसे-जैसे यह विवाद गहराता गया, एनवीडिया के बोर्ड ने मामले की तह तक जाने के लिए एक स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।

कांगो में सेना का खौफनाक फरमान! 66 सैनिकों को एक साथ मौत की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला



कांगो में 66 सैनिकों को युद्ध के मैदान से भागने, बगावत और आदेशों की अवहेलना के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। अब तक 381 सैनिकों को मृत्युदंड मिला। कांगो की सैन्य अदालत ने 71 सैनिकों के मुकदमे में 66 को मौत की सजा सुनाई, चार बरी हुए और एक को 10 साल जेल मिली। सैनिकों पर एम23 विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अपनी चौकियां छोड़कर भागने और आदेश नहीं मानने का आरोप था। कांगो में 2025 से अब तक 381 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी को फांसी नहीं दी गई है। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में सेना के 66 जवानों को मौत की सजा सुनाई गई है। इन सैनिकों पर युद्ध के मैदान से भागने, बगावत करने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी कीवू प्रांत के वालिकाले में 71 सैनिकों के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया था। इनमें से 66 को मृत्युदंड दिया गया, जबकि चार सैनिक बरी हो गए और एक को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। सेना के अधिकारियों के मुताबिक, इस मुकदमे का उद्देश्य पूर्वी कांगो में विद्रोही संगठनों के खिलाफ जारी सैन्य अभियानों के दौरान सैनिकों में अनुशासन कायम करना है। रिपोर्ट के अनुसार, इन सैनिकों को 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (FRN) के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपनी चौकियां छोड़ दी थीं और मोर्चे से भाग गए थे। एम23 विद्रोहियों के खिलाफ जारी है संघर्ष कांगो का पूर्वी इलाका दशकों से हिंसा और सशस्त्र संघर्ष का सामना कर रहा है। यहां सरकारी सेना और FRN नाम के विद्रोही गठबंधन के बीच लगातार लड़ाई जारी है।

कनाडा में 4 भालुओं को मिली मौत की सजा, लेकिन क्यों? वजह जान हो जाएंगे हैरान!



कनाडा में मां-बेटी की मौत के बाद DNA जांच में चार ग्रिजली भालुओं की पहचान हुई। वन्यजीव अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चारों को मार डाला। कनाडा में 48 वर्षीय मां और उनकी 20 वर्षीय बेटी की मौत के लिए एक मादा ग्रिजली और उसके तीन बच्चे जिम्मेदार पाए गए। DNA टेस्ट से चारों भालुओं की हमले में संलिप्तता की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने इसे दुर्लभ शिकारी हमला बताया। वन्यजीव विभाग ने लोगों की सुरक्षा का हवाला देकर चारों भालुओं को मारने का फैसला लिया। कनाडा में दो महिलाओं की जान लेने वाले चार ग्रिजली भालुओं को वन्यजीव अधिकारियों ने मार डाला है। इनमें एक मादा भालू और उसके एक साल के तीन बच्चे शामिल थे। DNA जांच में पुष्टि हुई कि इसी भालू परिवार ने पश्चिमी कनाडा में एक मां और उसकी वयस्क बेटी पर जानलेवा हमला किया था। अधिकारियों के मुताबिक, यह सामान्य शिकारी हमलों से अलग एक बेहद दुर्लभ मामला था। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश कोलंबिया कंजर्वेशन ऑफिसर सर्विस ने मंगलवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। मृत महिलाओं की पहचान 48 वर्षीय जेनी बाल्कारस और उनकी 20 वर्षीय बेटी सेला रीड के रूप में हुई है। दोनों के अवशेष वैंकूवर से करीब 1,000 किलोमीटर उत्तर में एक दूरदराज के इलाके में मिले थे। DNA जांच में हुई भालुओं की पहचान वन्यजीव अधिकारियों ने बताया कि DNA परीक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि हमले में एक मादा ग्रिजली और उसके तीन बच्चे शामिल थे। इंस्पेक्टर जेफ टायर ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया कि जांच में शिकार करने जैसे व्यवहार के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला बेहद दुर्लभ होता है। हालांकि, अधिकारियों को अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हमला किन परिस्थितियों में शुरू हुआ था।

सऊदी अरब में नौकरानी को 100 कोड़े मारने की सजा, शादी के बिना बच्चे को जन्म देने पर कोर्ट का फैसला



सऊदी अरब में बिना शादी बच्चे को जन्म देने पर केन्याई घरेलू सहायिका को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। फैसले से महिलाओं के अधिकारों पर बहस छिड़ी। सऊदी अरब की अदालत ने केन्याई महिला एस्थर वांजा मुथोनी को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। अगस्त 2025 में मिस्र के नागरिक से रिश्ते के दौरान बच्चे को जन्म दिया था। एक साल के निर्वासन की सजा भी सुनाई गई, बच्चे के पिता पर कार्रवाई नहीं होने से उठे सवाल। सऊदी अरब में शादी के बिना बच्चे को जन्म देने के मामले में एक केन्याई महिला को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। महिला सऊदी अरब में घरेलू सहायिका (हाउस हेल्प) के तौर पर काम करने गई थी।

अमेरिका में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, एक की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल



अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत और 10 से अधिक घायल हुए। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित फ्लैटबुश इलाके में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 10 से अधिक घायल; कई निर्माण श्रमिक अस्पताल में भर्ती। मलबे में फंसे एक व्यक्ति से बचाव दल का संपर्क, राहत और बचाव अभियान जारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन इलाके में बुधवार (11 नवंबर) दोपहर एक तीन मंजिला इमारत का हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। दमकल और बचाव दल की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं। यह हादसा ब्रुकलिन के फ्लैटबुश इलाके में बेडफोर्ड एवेन्यू और फ्लैटबुश एवेन्यू के पास हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, इमारत में आवासीय अपार्टमेंट के साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होती थीं। दोपहर करीब 4 बजे इमारत का एक हिस्सा ढह गया। घटना के बाद सामने आए वीडियो में इमारत के अंदर बने कमरों का हिस्सा बाहर से दिखाई दे रहा है। छत से लेकर पहली मंजिल तक के कई हिस्से खुले नजर आ रहे हैं। मलबे में फंसे व्यक्ति से संपर्क, बचाव अभियान जारी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दमकलकर्मी मलबे में फंसे एक अन्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। बताया गया है कि बचाव दल उस व्यक्ति के संपर्क में है। हादसे में घायल हुए कई निर्माण श्रमिकों को इलाज के लिए किंग्स काउंटी अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि, उनकी हालत को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) ने हादसे के बाद आसपास के इलाकों में यातायात बंद करने की सूचना जारी की है। पुलिस ने लोगों से बेडफोर्ड एवेन्यू और फ्लैटबुश एवेन्यू के आसपास जाने से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। गवर्नर और मेयर ने जताया दुख न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना जताई।

किरायेदार मकान खाली नहीं

समस्याओं और किराया समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करने वालों के मामलों में अब राहत मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत मुंबई के सभी 15 पुलिस जोन के पुलिस उपायुक्तों (DCP) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इस व्यवस्था के तहत अब संबंधित क्षेत्र के मकान मालिक किरायेदार से जुड़ी निर्धारित कानूनी शिकायतों के लिए अपने जोन के डीसीपी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। मुंबई पुलिस की पहली कार्रवाई इस व्यवस्था के तहत मुंबई पुलिस ने पहली बार किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। पश्चिम क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज शर्मा ने इसे नए किराया कानून के तहत पुलिस की पहली कार्रवाई बताया है। वहीं, जोन-8 के पुलिस उपायुक्त निमित गोयल ने इस व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा है कि इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। जोनल डीसीपी के पास मिलेगा कानूनी मंच अब तक ऐसे मामलों में मकान मालिकों को सक्षम प्राधिकारी के पास जाने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। नई व्यवस्था में संबंधित पुलिस जोन के डीसीपी को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। इससे मकान मालिकों को अपने क्षेत्र में ही निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। किरायेदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार महत्वपूर्ण इस व्यवस्था का उद्देश्य कानून के दायरे में रहकर मकान मालिकों को उनका कब्जा वापस दिलाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस बिना सुनवाई या कानूनी प्रक्रिया के किसी किरायेदार को मकान से बाहर कर सकती है। संबंधित प्राधिकारी को कानून के प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेना होगा। नई व्यवस्था से मकान मालिकों को किरायेदारों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एक स्थानीय और निर्धारित कानूनी मंच उपलब्ध होगा। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए संबंधित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रशासन का जोर इस व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर है, ताकि जरूरतमंद मकान मालिक इसका लाभ उठा सकें।

महाराष्ट्र में NCP के विलय की चर्चा

लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का फैसला उन्हें विश्वास में लिए बिना नहीं हो सकता। उनके बयान से यह साफ है कि भाजपा इस संभावित राजनीतिक बदलाव को महायुति के मौजूदा सत्ता समीकरण से अलग करके नहीं देख रही है। आखिरकार, अजित पवार की एनसीपी राज्य सरकार में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। विलय हुआ तो किसका कितना प्रभाव? दोनों एनसीपी गुटों के एक साथ आने की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व, संगठन और राजनीतिक हिस्सेदारी का होगा। शरद पवार का अनुभव और राजनीतिक नेटवर्क तथा अजित पवार गुट का मौजूदा संगठनात्मक ढांचा एक साथ आने पर पार्टी के भीतर नई व्यवस्था बनानी होगी। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी किसके पास रहती है और दोनों गुटों के नेताओं को किस तरह समायोजित किया जाता है। इसका असर महायुति के भीतर भी दिखाई दे सकता है। भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी के बीच सत्ता तथा राजनीतिक प्रभाव का मौजूदा संतुलन किसी भी बड़े संगठनात्मक बदलाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि, केवल विलय की चर्चा के आधार पर गठबंधन में किसी बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। विपक्ष के लिए भी अहम घटनाक्रम इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राजनीतिक भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। यदि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आते हैं, तो विपक्षी राजनीति में भी नए सवाल खड़े होंगे। वहीं, यदि विलय नहीं होता है, तो दोनों गुटों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी रह सकती है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीपी के दोनों गुटों की एकता केवल चर्चा तक सीमित रहेगी या इसके लिए कोई ठोस राजनीतिक पहल होगी। फिलहाल न विलय की आधिकारिक घोषणा हुई है और न ही भविष्य के सत्ता समीकरणों को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने आया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस चर्चा ने महायुति और विपक्ष, दोनों के राजनीतिक गणित को फिर बहस के केंद्र में ला दिया है।

धारावी में सभी को मिले 500 से

विरोध एक बार फिर तेज होने लगा है। परियोजना में पात्र और अपात्र निवासियों के वर्गीकरण, मकानों के आकार और पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। इन मांगों को लेकर धारावी के निवासी अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। धारावी बचाव आंदोलन समिति के बैनर तले 25 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में विशाल महामोर्चा निकाला जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) करेगी। आंदोलनकारियों का आरोप है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना में स्थानीय निवासियों के साथ पात्रता के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना है कि वर्षों से धारावी में रहने वाले लोगों को पात्र और अपात्र की श्रेणियों में बांटने के बजाय सभी प्रभावित परिवारों को पुनर्विकास का लाभ मिलना चाहिए। समिति की मांग है कि धारावी के सभी मौजूदा निवासियों को इसी इलाके में घर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें अपने पुराने सामाजिक और आर्थिक परिवेश से दूर न जाना पड़े। पात्र और अपात्र का वर्गीकरण खत्म करने की मांग महामोर्चे की तैयारियों को लेकर पीएमजीपी कॉलोनी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय में समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्थानीय निवासियों के प्रतिनिधियों ने पुनर्विकास परियोजना से जुड़ी समस्याओं, पात्रता के नियमों और मकानों के आकार को लेकर चर्चा की। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के बाद 25 नवंबर को आजाद मैदान में महामोर्चा निकालने का फैसला लिया गया। समिति के सदस्यों का कहना है कि पुनर्विकास का उद्देश्य धारावी के लोगों को बेहतर आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए। ऐसे में पात्र और अपात्र का वर्गीकरण कर स्थानीय निवासियों के बीच अंतर पैदा करना उचित नहीं है। सभी प्रभावित परिवारों को उनकी जरूरत और मौजूदा आवासीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय मिलना चाहिए। झो 25 नवंबर को आजाद मैदान में शक्ति प्रदर्शन 25 नवंबर को होने वाले महामोर्चे में धारावी के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों के शामिल होने की संभावना है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन के जरिए पुनर्विकास परियोजना से जुड़ी मांगों को सरकार और संबंधित प्रशासन के सामने रखा जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत पुनर्वास और उनके मौजूदा क्षेत्र में ही आवास देने की मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अब सभी की नजर 25 नवंबर को आजाद मैदान में होने वाले महामोर्चे पर टिकी है। पड़ीधारकों को 500 वर्गफुट का घर देने की मांग धारावी बचाव आंदोलन समिति ने पुनर्विकास के तहत मिलने वाले घरों के आकार को लेकर भी अपनी मांगें रखी हैं। समिति चाहती है कि झोपड़ीधारकों को पुनर्विकास के बाद 500 वर्गफुट क्षेत्रफल का मकान दिया जाए। वहीं, मनपा चाल और एसआरए में रहने वाले निवासियों के लिए 750 वर्गफुट के घर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि धारावी में बड़ी संख्या में परिवार लंबे समय से सीमित जगह में रह रहे हैं। ऐसे में पुनर्विकास के दौरान उन्हें पर्याप्त आवासीय क्षेत्र मिलना जरूरी है। केवल इमारतों का निर्माण करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रभावित परिवारों की वास्तविक जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा।

सिंहगढ़ एजुकेशन सोसायटी पर हाईकोर्ट

मिले हैं। 60.65 करोड़ रुपये देने का वादा भी पूरा नहीं 6 नवंबर को संस्था के प्रबंधकीय ट्रस्टी मारुति नवले ने कर्मचारियों को 60 करोड़ 65 लाख 6 हजार 436 रुपये देने का आश्वासन दिया था। भुगतान 7 नवंबर तक करने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों को राशि नहीं मिली। इस पर हाईकोर्ट ने संस्था को दिए गए न्यायिक आश्वासन का उल्लंघन माना। फंड के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अदालत ने सवाल उठाया कि जब संस्था के 44 संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और विद्यार्थियों से नियमित फीस वसूली जा रही है, तो कर्मचारियों का वेतन क्यों रोका गया? पीठ ने आशंका जताई कि कर्मचारियों के वेतन की राशि दूसरे कारोबारों में लगाई गई हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेश में धन भेजे जाने की आशंका की भी जांच होगी। स्कूलों और तकनीकी संस्थानों पर कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने संस्था को मिला अंतरिम संरक्षण समाप्त कर दिया है। शिक्षा विभाग को 13 स्कूलों की मान्यता रद्द करने संबंधी कार्रवाई और तकनीकी संस्थानों में प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें दूसरी स्कूलों में समायोजित करने की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। 19 नवंबर को पेश होगी जांच रिपोर्ट अदालत ने मारुति नवले का पासपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने और अन्य ट्रस्टियों के पासपोर्ट भी अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया है। EPF प्राधिकरण संस्था की वैधानिक जिम्मेदारियों की जांच करेगा। CBI, ED और आयकर विभाग को 19 नवंबर को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी।

एसीबी की कार्रवाई में 3.32 करोड़

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। ओहदे के हिसाब से बात करें तो रिश्वत लेने के इन मामलों में क्लास-III के सरकारी कर्मचारी सबसे आगे रहे हैं, जिनकी कुल संख्या 437 है, जबकि क्लास-II, क्लास-1 और क्लास-IV के कर्मचारी भी पीछे नहीं हैं। नासिक रेंज में सबसे अधिक 128 मामले दर्ज किए गए रेजवार आंकड़ों पर नजर डालें तो नासिक रेंज में सबसे अधिक 128 ट्रैप केस दर्ज किए गए, जबकि पुणे में 106, छत्रपति संभाजीनगर में 97, ठाणे में 81, अमरावती में 62, नागपुर में 57, नांदेड में 48 और मुंबई में 33 मामले सामने आए। इसके अलावा एसीबी ने इस साल आय से अधिक संपत्ति के भी 11 गंभीर मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कुल 27.22 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है और इस मौर्चे पर भी रेवेन्यू विभाग के अधिकारी सबसे आगे पाए गए हैं। 3.32 करोड़ रुपये की रिश्वत का खुलासा 612 ट्रैप मामलों में कुल 3.32 करोड़ रुपये की रिश्वत लिए जाने का पर्दाफाश हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा 73.04 लाख रुपये की रिश्वत अकेले पुलिस अधिकारियों से जुड़ी पाई गई। वन विभाग (53.86 लाख), रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स (40.17 लाख), सार्वजनिक निर्माण विभाग (22.42 लाख), सेल्स टैक्स (21.86 लाख), पंचायत समिति (20.74 लाख) और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाख), एमएसईडीसीएल (15.25 (14.48 लाख रुपये) का नंबर आता है।

मुंबई में पटाखे फोड़ने पर खूनी

शुरू हुआ था विवाद पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दीपावली के मौके पर अंधेरी पूर्व के मरोल कृष्णा नगर इलाके में गुप्ता परिवार की छोटी बच्ची गली में खाली जगह पर पटाखे फोड़ रही थी। इसी दौरान बादल गोस्वामी और उसकी गैंग ने पटाखे फोड़ने का विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने गुप्ता परिवार के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। मारपीट में दंपति और उनकी छोटी बच्ची भी घायल विवाद इतना बढ़ गया कि बादल गोस्वामी और अन्य लोगों ने मिलकर गुप्ता परिवार पर हमला कर दिया। 8 से 10 लोगों ने महिला को जमीन पर गिराकर डंडे से बेरहमी से पीटा। पत्नी को बचाने पहुंचे पति को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा और उस पर भी हमला कर दिया। इस मारपीट में दंपति के साथ उनकी बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में मुंबई की एमआईडीसी पुलिस ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गैंग के कथित सरगना बादल गोस्वामी के साथ धर्मेंद्र राजभर, जितेंद्र राजभर और श्याम नारायण गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं, फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। विलेपार्ले में भी हुई थी हत्या की घटना इससे पहले मुंबई शहर के विलेपार्ले में दीपावली की रात को पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार और एक नाबालिग को हिरासत में लिया था। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 8 नवंबर की रात करीब 11 बजे विलेपार्ले पश्चिम के वी.एम. रोड स्थित सानिध्य बिल्डिंग के सामने एचडीएफसी बैंक के पास फुटपाथ पर यह घटना हुई थी।

पृष्ठ 1/8 का शेष

मुंबई लोकल में 20 वर्षीय युवती

नायगांव स्टेशन पर पटरी पर धकेलने का आरोप है। ट्रेन की चपेट में आने से उसका बायां हाथ कोहनी से काटना पड़ा, जबकि सिर में 16 टांके आए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के परिवार ने मामले में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग की है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को पटरी पर धकेला मुंबई शहर की लोकल ट्रेन में महिला सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। बोरिवली से विरार की ओर जा रही लोकल ट्रेन में एक युवती के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर आरोपी ने उसे नायगांव रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे धकेल दिया। इस हादसे में युवती का बायां हाथ ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया और उसे कोहनी से काटना पड़ा। घटना 4 नवंबर की बताई जा रही है। गलत तरीके से छूने पर हुआ विवाद पीड़िता के अनुसार, वह बोरिवली से नायगांव जाने के लिए लोकल ट्रेन में सवार हुई थी। नायगांव स्टेशन आने के दौरान एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत तरीके से छूने की हरकत की। युवती ने इसका विरोध किया और आरोपी को चप्पल से मारा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हुई। पीड़िता का आरोप है कि स्टेशन पर उतरने के बाद भी आरोपी ने उसे परेशान किया। विवाद के दौरान आरोपी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। इससे वह दो डिब्बों के बीच से रेलवे ट्रैक पर गिर गई। वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी लोकल ट्रेन चल पड़ी और उसका बायां हाथ पहिए के नीचे आ गया। सिर में 16 टांके, हाथ कोहनी से काटना पड़ा हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके सिर में भी गंभीर चोट आई, जिसके लिए 16 टांके लगाने पड़े। हाथ की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे कोहनी से काटना पड़ा। पीड़िता ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वह अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली अकेली सदस्य थी। अब एक हाथ खराब होने के कारण उसके सामने भविष्य को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उसने आरोपी को कड़ी सजा देने और न्याय दिलाने की मांग की है। आरोपी गिरफ्तार, धारा 109 जोड़ने की मांग घटना के बाद आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था। 6 नवंबर को भाईंदर रेलवे पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 117(2) और 352 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, हत्या के प्रयास से संबंधित धारा 109 नहीं लगाए जाने पर पीड़िता के परिवार ने नाराजगी जताई। मनसे पदाधिकारी सचिन पोपळे के अनुसार, परिवार ने मनसे पदाधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर धारा 109 जोड़ने की मांग की। उनके मुताबिक, अधिकारियों ने इस संबंध में अदालत को पत्र देकर आवश्यक धारा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। लोकल में महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल इस घटना के बाद मुंबई लोकल ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। मनसे पदाधिकारी ने महिलाओं से सतर्क रहने और ऐसी घटना होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। पीड़िता और उसके परिवार की मांग है कि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई हो और आरोपी को सख्त सजा मिले।

मुंबई मड आइलैंड की पार्टी

बाद छात्रा बेहोश हो गई। आरोप है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद छात्रा ने नवंबर के पहले सप्ताह में अपने माता-पिता को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर जुहू पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जीरो एफआईआर के बाद जुहू पुलिस को जांच घटनास्थल मालवणी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 74, 123 और 3(5) के तहत पहले मालवणी में जीरो एफआईआर दर्ज की गई। बाद में पीड़िता के माता-पिता के अनुरोध पर आगे की जांच जुहू पुलिस को सौंप दी गई। छत्तीसगढ़ से आरोपी गिरफ्तार जांच के दौरान जुहू पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी मुंबई छोड़कर छत्तीसगढ़ स्थित अपने पैतृक गांव चला गया है। इसके बाद पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ भेजी गई। टीम ने वहां पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद पुलिस उसे मुंबई लेकर आई। आरोपी को मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। एक अन्य संदिग्ध की भूमिका की जांच इस मामले की एफआईआर में एक अन्य संदिग्ध का नाम भी शामिल है। हालांकि, कथित घटना में उसकी भूमिका क्या थी और वह इसमें शामिल था या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही पार्टी में मौजूद कॉलेज के अन्य छात्रों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

राकांपा के दोनों गुटों का विलय, सांसद सुप्रिया सुले बोलीं- अजीत पवार के निधन से बंद हो गया अध्याय

राकांपा (शरद गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पार्टी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई अजित पवार के निधन के साथ ही उनके लिए विलय का अध्याय समाप्त हो गया। सुप्रिया सुले के मुताबिक, उन्हें विलय का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने स्वीकार किया कि अजित पवार ने निधन से पहले दोनों गुटों को मिलाने की पहल की थी, लेकिन अब इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय की किसी भी बातचीत से स्पष्ट इन्कार कर दिया।

मुंबई में BMC कार्यालय और PNB बैंक को बम से उड़ाने की धमकी

ई-मेल से मचा हड़कंप; जांच में कुछ नहीं मिला

मुंबई के BMC मुख्यालय और पंजाब नेशनल बैंक को बम की धमकी वाला ई-मेल मिला। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने ई-मेल को फर्जी बताया। मुं Break-ing मुंबई में शुक्रवार को मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) कार्यालय और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बरतते हुए जांच की। हालांकि, जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। डीसीपी आर. रागसुधा ने बताया कि बीएमसी कार्यालय और पीएनबी बैंक को बम की धमकी वाला फर्जी ई-मेल प्राप्त हुआ था। दोनों स्थानों पर जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने की फर्जी ईमेल की पुष्टि मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि यह एक फर्जी ईमेल था। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर ईमेल के सोर्स की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की मदद से आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा



है। फिलहाल दोनों जगहों पर स्थिति सामान्य है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बई के बीएमसी कार्यालय और पीएनबी बैंक को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुरक्षा एजेंसियों की गहन जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने इस धमकी भरे ईमेल को पूरी तरह फर्जी करार देते हुए मामला दर्ज किया। हले भी मिली है फर्जी धमकियां बता दें कि इससे पहले भी देश कई राज्यों में इस तरह के फर्जी धमकी भरे ईमेल या पत्र बरामद हो चुके हैं। धमकी मिलने के बाद स्कूलों, सरकारी इमारतों को खाली कराकर जब जांच की गई तो ये धमकी फर्जी पाई गई। इतना ही नहीं, देश के कई विमानों में भी धमकी भरे नोट्स मिल चुके हैं। फ्लाइट को हाइजैक करने की धमकी इससे पहले 11 नवंबर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई शहर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को हाइजैक करने की धमकी मिली थी। इस घटना के बाद हवाई अड्डे पर तनाव का माहौल बन गया और विमान की गहन तलाशी की गई थी। अधिकारियों के अनुसार, उड़ान भरने की तैयारी कर रहे विमान के पायलट को धमकी की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी जानकारी दी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान के शौचालय में एक नोट मिला था, जिसमें विमान को हाइजैक करने की चेतावनी दी गई थी। यह नोट किसी व्यक्ति की नजर में आने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी।

मुंबई में पटाखे फोड़ने पर खूनी विवाद! महिला को जमीन पर गिराकर डंडों से पीटा, पति और बच्ची भी घायल; 4 गिरफ्तार



मुंबई के अंधेरी पूर्व के मरोल कृष्णा नगर में दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। 8-10 लोगों ने दंपति और उनकी बच्ची पर हमला किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के अंधेरी पूर्व में पटाखे फोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। आरोपियों ने महिला और उसके पति तथा बच्ची पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को दबोचा। मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित मरोल कृष्णा नगर इलाके में दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक गैंग ने पति-पत्नी और उनकी छोटी बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। 8 से 10 लोगों के गैंग ने महिला को जमीन पर गिराकर डंडे से बेरहमी से पिटाई की। जब महिला का पति उसे बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी जमकर पीटा। इस हमले में पति-पत्नी और उनकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए जोगेश्वरी स्थित बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटाखों को लेकर ...शेष 7 पर

एसीबी की कार्रवाई में 3.32 करोड़ की रिश्वत का खुलासा, राजस्व विभाग के सबसे ज्यादा मामले

महाराष्ट्र एसीबी ने जनवरी से नवंबर 2026 तक 612 ट्रैप केस और 875 लोगों पर मामला दर्ज किया। राजस्व विभाग में सबसे अधिक केस दर्ज। महाराष्ट्र में 11 महीनों में 612 ट्रैप केस, 875 आरोपी। 3.32 करोड़ की रिश्वत का खुलासा, पुलिस विभाग सबसे आगे। आय से अधिक संपत्ति के 11 मामलों में 27.22 करोड़ की संपत्ति उजागर। महाराष्ट्र में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने इस साल जनवरी से नवंबर 2026 के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। राज्यभर में फैले भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ने के लिए एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई बड़े खुलासे किए



हैं। इस अवधि में कुल 612 ट्रैप केस दर्ज किए गए हैं। रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड विभाग के अधिकारियों पर सबसे अधिक केस दर्ज हुए। जबकि इन मामलों में कुल रिश्वत की रकम 3.32 करोड़ रुपये रही। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के 11 केस भी दर्ज किया है। जिनमें कुल 27.22 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन मामलों में सरकारी महकमों के भीतर फैले भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खुलकर सामने आया है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। एसीबी की इन सुनियोजित छापों और कार्रवाइयों में कुल 875 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 146 प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल हैं, जो दलाली या अन्य माध्यमों से इसमें लिप्त थे। जब विभागवार आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, तो रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स विभाग के अधिकारियों पर सबसे अधिक 149 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस विभाग में 98, पंचायत समिति में 63 और बिजली वितरण कंपनी एमएसईडीसीएल में 43 केस सामने आए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शिक्षा विभाग, वन विभाग और ...शेष 7 पर

मुंबई मड आइलैंड की पार्टी में दोस्त को नशीला ड्रिंक पिलाकर यौन उत्पीड़न



22 वर्षीय युवक छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

मुंबई के मड आइलैंड में पार्टी के दौरान छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न का आरोप। जुहू पुलिस ने 22 वर्षीय कॉलेज छात्र को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। मुंबई में 29 अक्टूबर को मड आइलैंड की पार्टी में हुई घटना। छात्रा की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका यौन उत्पीड़न आरोपी 22 वर्षीय कॉलेज छात्र को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया। एक अन्य संदिग्ध की भूमिका की भी पुलिस कर रही जांच। मुंबई के मालाड स्थित मड आइलैंड में 29 अक्टूबर को आयोजित एक पार्टी के दौरान छात्रा की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप है। मामले में जुहू पुलिस ने विले पार्ले के एक नामी कॉलेज के 22 वर्षीय छात्र को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस एक अन्य संदिग्ध और पार्टी में मौजूद छात्रों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बेहोश कर किया यौन उत्पीड़न मुंबई शहर के मालाड पश्चिम स्थित मड आइलैंड में आयोजित एक पार्टी के दौरान कॉलेज की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि पार्टी में छात्रा की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया और उसके बेहोश होने के बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में पुलिस ने विले पार्ले स्थित एक नामी कॉलेज के 22 वर्षीय छात्र को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद मुंबई छोड़कर अपने पैतृक गांव चला गया था। पार्टी में ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ पुलिस के अनुसार, 29 अक्टूबर को मड आइलैंड में कॉलेज के कुछ छात्रों ने पार्टी आयोजित की थी। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर छात्रा के पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला दिया। उसे पीने के ...शेष 7 पर

मुंबई लोकल में 20 वर्षीय युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर चलती ट्रेन के नीचे धकेला; कट गया बायां हाथ



मुंबई लोकल में नायगांव स्टेशन पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को पटरी पर धकेलने का आरोप। ट्रेन की चपेट में आने से बायां हाथ कोहनी से काटना पड़ा, आरोपी गिरफ्तार। नायगांव स्टेशन पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को पटरी पर धकेलने का आरोप। ट्रेन की चपेट में आने से बायां हाथ कोहनी से काटना पड़ा; सिर में 16 टांके। आरोपी गिरफ्तार; परिवार ने हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग की। मुंबई लोकल ट्रेन में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 4 नवंबर को एक युवती को ...शेष 7 पर

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486